THE WORLD BANK

Working for a World Free of Poverty

क्षेत्रीय झलकियां

वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2006
दक्षिण एशिया

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति

निर्धनता कम करने की राह पर अग्रसर

- दक्षिण एशिया ने आय निर्धनता कम करने की दिशा में सुदृढ़ प्रगति की है, जिससे यह प्रतिदिन $1 से कम पर जीने वाली आबादी के हिस्से को 2015 तक आधा करने का लक्ष्य पूरा करने की राह पर लगभग बढ़ चुका है।

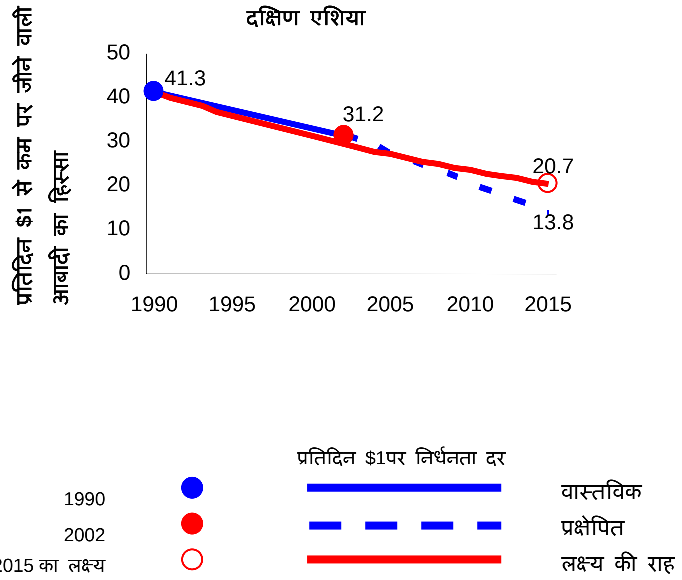

- तीव्र आर्थिक वृद्धि इसका एक प्रमुख कारक रही है, और भारत से इतर कम आय वाले दक्षिण एशियाई देशों ने 2005 में 4.8 प्रतिशत वृद्धि हासिल की। भारत और पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि 2005 में आठ प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है।
- दक्षिण एशियाई देशों को निजी क्षेत्र की वृद्धि के लिए निवेश के माहौल की निगरानी करने और उसे सुधारने की ज़रूरत होगी। दक्षिण एशिया के कई देशों में एक ही फ़र्म के विभिन्न स्थलों के बीच उत्पादकता में होने वाले अंतर का 80 प्रतिशत कारण निवेश के क्षेत्रीय माहौल की स्थिति है।
- निवेश के माहौल पर विश्व बैंक के सर्वेक्षणों में 75 देशों के उद्यमियों द्वारा गिनाई गई बाधाओं में नियामक नीतियों और उनके क्रियान्वयन की अनिश्चितता अब भी शीर्ष पर बनी हुई है। लातविया या स्लोवेनिया के 10 प्रतिशत के मुकाबले बांग्लादेश में 85

प्रतिशत फ़र्मों का कहना है कि कर निरीक्षक मुलाकातों के दौरान 'तोहफ़े' पाने की उम्मीद करते हैं।

'मानव विकास' के सभी लक्ष्यों पर प्रगति बहुत धीमी है

- क्षेत्र का अधिकांश भाग पौष्टिकता के लक्ष्य, यानी, पांच वर्ष से कम आयु के कम वज़न वाले बच्चों की संख्या के आधार पर भूख से पीड़ित बच्चों की संख्या आधी करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है, जिसका आंशिक कारण समुदाय-आधरित पौष्टिकता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक विस्तारित करना है।
- पूरे विकासशील विश्व में, बांग्लादेश जैसे जिन देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुदृढ़ एकीकृत योजनाएं चल रही हैं वे स्वास्थ्य क्षेत्र की अपनी प्राथमिकताओं को बिगाड़े बिना वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों की सहायता का उपयोग करने में औरों के मुकाबले अधिक सफल रहे हैं।
- लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की क्षेत्रीय पूर्णता दर अब भी लड़कों के मुकाबले 15 प्रतिशत से भी अधिक नीचे है; केवल 47 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक विद्यालयों में जाती हैं। बांग्लादेश में, जहां अब सभी लड़कियां प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत हैं, सरकार और अन्य द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर दिए गए ज़ोर (जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं) के कारण शिक्षा में लैंगिक दूरी उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि हर चार लड़कों पर तीन लड़कियां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जाती हैं।
- क्षेत्रीय मातृत्व मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार (1990 में प्रशिक्षित कर्मियों की देखरेख में 27 प्रतिशत प्रसव के मुकावले 2003 में 38 प्रतिशत) के बावजूद, दक्षिण एशिया इस लक्ष्य से अब भी काफी पीछे है।

आधारभूत संरचना में सुधार बहुत धीमा है

- निरपेक्ष अर्थ में, दक्षिण एशिया ने आधारभूत संरचना में सुधार करने में प्रगति की है, लेकिन पानी, बिजली और टेलीफोन तक पहुंच का विस्तार दो प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए पर्याप्त गति से नहीं हो रहा है।

शासन की निगरानी और सुधार

- **प्रभावी शासन की निरंतरता के सहायक कारकों** में शामिल हैं -- रोक एवं नियंत्रण की उपयुक्त संस्थाएं जैसे कि जवाबदेह स्थानीय प्रशासन और स्वतंत्र प्रेस, नागरिकों एवं फ़र्मों की आवाज़ें, तंत्र के भीतर स्पष्ट नियम एवं अपेक्षाएं, कार्यप्रदर्शन की निगरानी के लिए पारदर्शी सूचनाएं और क्रियान्वयन के ऐसे तंत्र जो सफलता को पुरस्कृत करते हैं तथा असफलता पर ध्यान देते हैं।

- पूरे विकासशील विश्व में, स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणालियों में सबसे व्यापक हानियां और दुरुपयोग स्पष्टतः अगली पंक्तियों में होते हैं जहां सेवा प्रदाता या तो कार्य से अनुपस्थित रहते हैं या ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान मांगते हैं जो कानूनी तौर पर निशुल्क हैं। भारत में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि चिकित्सा केंद्रों की बंदी का कोई ढर्रा नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि किसी रोगी को सेवा प्रदाता मिलने की संभावना अनिश्चित रहती है।

- भारत ने हाल में इस बात के दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि सेवा प्रदाय की अगली पंक्तियों में **जवाबदेही बेहतर बनाने के लिए सूचना का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।**
    - बेंगलूर, भारत, में नागरिकों के एक समूह ने जनसंख्या के दबाव से त्रस्त एक गतिशील शहर में सार्वजनिक सेवाओं पर वर्षों से कायम निष्क्रियता की स्थिति से तंग आकर, **सार्वजनिक सेवाओं पर एक उपयोगकर्ता सर्वेक्षण-आधारित 'रिपोर्ट कार्ड'** की शुरुआत की। 1994 और 2003 के बीच कराए गए तीन सर्वेक्षणों से पता चला कि सेवा प्रदाय की गुणवत्ता के प्रति नज़रिए में असाधारण बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि नकारात्मक प्रचार ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया। नागरिकों की सक्रियता और एजेंसियों के साथ संवाद में बढ़ोत्तरी हुई, और इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने कार्रवाई करने तथा एजेंसियों को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। बेंगलूर में शुरू की गई इस पद्धति को ब्राज़ील, फिलिप्पींस, यूक्रेन और तुर्की सहित कई देशों में लागू किया गया है।
    - राजस्थान में, राज्य के 2001 के सूचना के अधिकार कानून के आधार पर आगे काम करते हुए, किसान-मज़दूर शक्ति संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुनवाइयां आयोजित कीं जिनमें राशन के अनाज के वितरकों के कागज़ात में दिए गए आंकड़ों का प्राप्तकर्ताओं के राशन कार्डों से मिलान किया गया। अस्पतालों का **सामाजिक ऑडिट** भी कराया गया जिस दौरान चिकित्सा रिकार्ड के आंकड़ों का रोगियों के वास्तविक अनुभवों से मिलान किया गया। दोनों ही मामलों में भारी अंतर पाए जाने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, ग़बन और कुप्रबंधन की जांच कराई गई तथा इनके साक्ष्य भी मिले।